initiated measures to revamp the Public Distributon System (PDS) to improve the reach of PDS commodities in identified areas. The Central Government in consultation with the State Governments and U.T. Admnistrations, identified about 1700 blocks which are covered by various area specific programmes such as Drought Prone Areas Programmes, Desert Development Programmes, Integrated Tribal Development Projects and certain Designated Hill Areas. The State Governments have been requested to initiate steps to ensure delivery of PDS commodities at Fair Price Shops in these identified areas. They propose to open about 11000 Fair Price Shops, issue ration cards to people who have not been provided one so far. The estimated population likely be served by this scheme is around 167 millions.

As a part of the scheme State Governments/UT. Administrations have been requested to eliminate bogus ration cards and set up village level Vigilance Committees to monitor the distribution of PDS commodities at the FPSs. Additional commodities such as puleses, tea, soaps and iodised salt are also proposed to be distributed using the PDS outlets, whaerever necessary.

छापों के दौरान गेहूं तथा चावल के अपार भंडार का बरामद किया जाना।

443. श्री हरवंश सिंह इंसपाल :
डा० जी० विजय मोहन रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हाल ही में मारे गये छापों के दौरान गेहूं तथा चावल के अपार भंडार बरामद किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जमाखोरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इस तरह के छापे दिल्ली से बाहर भी मारे जायेंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में दिल्ली प्रशासन के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा 18 व्यापारियों के परिसरों की जांच के दौरान चावल की 2,91,857 क्विंटल मात्रा बरामद की गई है। दो चावल विक्रेताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस ने खाद्यान्न व्यापारियों के परिसरों/उचित दर दुकानों/मिट्टी के तेल के डिपुओं और खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों के संबंध में 46 जांच कार्यवाहियां भी की जिसके परिणामस्वरूप फरवरी, 92 के पहले पखवाड़े में 8 मामलों में प्रथम रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

(ग) राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और इसी तरह के कानूनों के उपबंधों के तहत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और अन्य कदाचारों में लिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई कर रहे हैं।

Price rise after the presentation of the Budget

444. SHRI GURUDAS DAS GUPTA :
SHRI CHATURNAN MISHRA :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether wholesale prices of many items rose after the presentation of budget for 1991-92.;

(b) if so, the reaons therefor ; and

(c) the steps taken by the Government to contain the price rise ?